Shri Narendra Singh Mahida: The Raj Ratna Mills, Petlad, which is in my constituency, has been closed for the last 1½ years. A committee was appointed under the chairmanship of Shri Oza who was a member of this House, and its report has been submitted to Government. What reply has the Government of India given to the Gujarat Government in this connection?

Shri Dinesh Singh: The difficulty in all these questions is that hon. Members wish to go into cases of individual mills. If they would let me know that they wish to go into the cases of individual mills, I will very gladly give the facts. But it is difficult for me to recollect all the reports that have been submitted or other facts about individual mills.

Shri P. Ramamurti: Pondicherry is directly under the Central Government. In connection with the affairs of the Bharati Textile Mills, Pondicherry, a committee of M.Ps. was appointed and that committee had recommended ten months ago that the mill has to be taken over by the Central Government. What do Government propose to do with regard to the recommendation of that parliamentary committee?

Shri Dinesh Singh: I am sorry the hon. Member did not know the full facts. The mill was taken over in June 1966 and it is functioning from February 1967.

श्री द्वा० ना० तिवारी: अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कारपोरेशन बनने के बाद ऐसी मिलों को परमानेन्टली ले लिया जायेगा जिन में घाटा होता है या जिसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी मिलों के लेने के बाद सरकार उन को कम्पन्सेशन देने की बात भी सोचती है ? क्योंकि मिल को ले कर ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा कि मिलों को घाटा न हो और और उन का प्रबन्ध अच्छा हो जाये ।

श्री दिनेश सिंह : मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि । जितनी मिलें हैं वे सब हम ले लेंगे यह मैंने नहीं कहा है । जिन को मुनासिब समझेंगे उनको हम लेंगे । जो मुआवजा देना होगा या जो लिक्विडेशन प्राइस होगी या और जो तरीका होगा उसको यहां पर माननीय सदस्य तय करेंगे, उसके हिसाब से काम होगा ।

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने बताया है कि टैक्सटाइल का कारपोरेशन के गठन के लिये एक विधेयक वह प्रस्तुत करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि टैक्सटाइल कारपोरेशन की रचना करते समय क्या मंत्री महोदय इस बात का ख्याल रखगे कि शासकीय खर्चा ज्यादा होने से वह एक दूसरा सफेद हाथी न बनें । दूसरी बात यह है कि जो माल पैदा होगा उसका वितरण और बिक्री का जब तक इंतजाम नहीं होगा टैक्सटाइल कारपोरेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका भी कोई इंतजाम इस विधेयक के द्वारा आप करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : वितरण का तो अभी कोई विचार नहीं किया गया है और न कोई इसकी आवश्यकता हम समझते हैं । लेकिन पहला सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उस पर हम जरूर ध्यान देंगे ।

Price of Woollen Yarn

*244. **Shri Abdul Ghani Dar:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the woollen yarn is being sold in the Indian market at a rate double than the control price;

(b) if so, the action being taken against those persons or firms who evade surcharge, income tax, sales-tax by selling the yarn in black-market; and

(c) the number of persons who have been arrested and prosecuted during the last six months in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) There is a price control on worsted yarn produced from raw wool imported under 'actual users' licences. This yarn is, however, also subject to distribution control and is intended for release to consumers in the decentralised sector against permits and is not available in the open market. Indian woollen yarn which is also subject to price control is not selling at a higher price. Worsted yarn produced from wool imported under Export Promotion Licences or under National Defence Remittance Scheme licences, are not subject either to price control or Distribution Control.

(b) and (c). Do not arise.

श्री अब्दुल गनी डार : अभी मंत्री जी ने फरमाया है कि ऊनी धागा जो इम्पोर्ट होता है वह ज्यादा कीमत पर नहीं बिकता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि जो रेट मुकर्रर हुआ है उस से तकरीबन दुगने भाव पर इस वक्त ऊनी धागा बिकता है। मैं राज्य सभा का पहले सदस्य था। तब भी इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया था और कई दफा दिलाया गया था। सरकार ने इसको माना भी था कि ऊंचे भाव पर वह बिकता है। मुश्किल यह है कि अब वह यहां पर फरमा रहे हैं कि नहीं बिकता है। इसको बिकने की इजाजत सरकार देती है और कहती है कि हम उनको इसेंटिव देते हैं कि वे एक्सपोर्ट करें और वहां से टापवूल्स आयें। तकरीबन दस रुपये फी पाउंड ऊनी धागा यहां मंहगा बिकता है साथ ही इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और बाकी चीजें जो सरकार के पास आनी चाहियें नहीं आती हैं। क्या यह सब सही नहीं है?

[**شری عبدالغنی ڈار :** ابھی منسٹری جی نے فرمایا ہے کہ اونی دھاگا جو امپورٹ ہوتا ہے وہ زیادہ قیمت پر نہیں بکتا ہے - میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جو ریٹ مقرر ہوا ہے اس سے تقریباً دگنے بھاؤ پر اس وقت اونی دھاگا بکتا ہے - میں راجیہ سبھا کا پہلے سدسیہ تھا - تب بھی اس طرف سرکار کا دھیان دلایا گیا تھا اور کئی دفعہ دلایا گیا تھا - سرکار نے اس کو مانا بھی تھا کہ اونچے بھاؤ پر وہ بکتا ہے - مشکل یہ ہے کہ اب وہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نہیں بکتا ہے - اس کو بکنے کی اجازت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ان کو انسینٹو دیتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کریں اور وہاں سے ٹاپ وولز آئیں - تقریباً دس روپیہ فی پاؤنڈ اونی دھاگا یہاں مہنگا بکتا ہے - ساتھ ہی انکم ٹیکس ، سیلز ٹیکس اور باقی چیزیں جو سرکار کے پاس آنی چاہئیں نہیں آتی ہیں - کیا یہ سب صحیح نہیں ہے -]

श्री शफी कुरेशी : मैंने अर्ज किया है कि जो हम बाहर से वूल मंगाते हैं, मैरिनों टाइप उस पर तो तक्सीम का भी और कीमत का भी कंट्रोल है, लेकिन जो वूल एक्सपोर्ट प्रोमोशन स्कीम्ज के तहत पहले आई थी या नेशनल डिफेंस रिमिटेंस स्कीम के तहत आई है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, न उसकी कीमत पर और न उसकी तक्सीम पर। हो सकता है कि उस कीमत पर चूंकि कंट्रोल गवर्नमेंट ने नहीं किया है और दूसरी जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड वूल है उस में थोड़ा फर्क हो। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की कंट्रोल्ड

बैराइटीज का ताल्लुक है, उनकी कीमतें बाजार में वही हैं जोकि गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है।

श्री अब्दुल गनी डार : क्या आपको यह मालूम है कि टैक्सटाइल कमिश्नर ने जो वूलन स्पिनिंग मिल्ज हैं आपस में उन में एक बड़ा मतभेद रखा है ? किसी को सेंट परसेंट वीव यार्न बनाने की इजाजत दी है किसी को 60 परसेंट होजरी यार्न बनाने की इजाजत दी है और कुछ जो डिजर्व करती हैं उनको बहुत कम बनाने की इजाजत दी है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जैसे बिड़ला साहब की मिल है उस मिल को सेंट परसेंट यार्न वीव करने की इजाजत दे दी है। और साथ ही यह भी इजाजत दे दी है कि वे अपने लिए धागा खुद ही वहां पर वीव भी कर लें। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा करने से क्या ब्लैक मार्किट के चांस ज्यादा नहीं हो जाते हैं और कीमतें ऊंची नहीं चली जाती हैं। साथ ही क्या यह जो डिसक्रिमिनेशन होता है इसकी तरफ सरकार ने टैक्सटाइल कमिश्नर का ध्यान दिलाया है ?

[شری عبدالغنی ڈار : کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ٹیکسٹائل کمشنر نے جو سپننگ ملز ہیں آپس میں ان میں ایک بڑا مت بھید رکھا ہے۔ کسی کو سینٹ پر سینٹ ویو یارن بنانے کی اجازت دی ہے کسی کو ساٹھ پرسنٹ ہوزری یارن بنانے کی اجازت دی ہے اور کچھ جو ڈیزرو کرتی ہیں ان کو بہت کم بنانے کی اجازت دی ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جیسے برلا صاحب کی مل ہے اس مل کو سینٹ پر سینٹ یارن ویو کرنے کی اجازت دے دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے لئے دھاگا خود ہی وہاں پر ویو بھی کر لیں - میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کرنے سے کیا بلیک مارکیٹ کے چانس زیادہ نہیں ہو جاتے ہیں اور قیمتیں اونچے نہیں چلی جاتی ہیں - ساتھ ہی کیا یہ جو ڈسکریمینیشن ہوتا ہے اس کی طرف سرکار نے ٹیکسٹائل کمشنر کا دھیان دلایا ہے -]

श्री शंकर कुरेशी : धागा तीन सैक्टर्ज को जाता है, वीविंग सैक्टर में जाता है, होजरी सैक्टर में जाता है और निटिंग सैक्टर में जाता है। मुमकिन है कि किसी किसी जगह पर किसी किसी कारखाने के साथ इमतयाज हो गया हो और उनको दस या पांच परसेंट एक खास धागा बनाने की ज्यादा इजाजत दे दी गई हो। लेकिन यह मामला इस वक्त हमारे जेर गौर है और मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह जो फर्क है इसको चन्द दिनों के अन्दर अन्दर खत्म कर दिया जाएगा।

Shri R. K. Birla: My friend Mr. Abdul Ghani Dar has said something about a mill owned by Birla in Jamnagar. I happen to be the chairman of the board of directors of that mill. Mr. Abdul Ghani was not right in saying that this mill is making 100 per cent woollen yarn.

श्री भोगेन्द्र झा : इनसे यह सफाई ले ली जाए कि कौन मिनिस्टर बिड़ला से रुपया लेते हैं। अपने मुंह से यह कह दें तो झगड़ा खत्म हो जाए।

Mr. Speaker: Order, order. He has not put one question. As an hon. Member of this House, he has a right to put a question. He is an hon. Member like any of us.

Shri Swell: We have a right to listen to every Member. Whenever any Member puts across something.

those who do not want to hear him need not, but they should at least allow him.

Shrimati Sharda Mukerjee: Parliament is not the forum for pleading any individual's private case, be he the managing director or otherwise. He can talk of general problems but he could not talk of his company. Is this a new precedent we are setting up?

Mr. Speaker: Perhaps for the first time he is putting a question in this House. He saw that every Member has a preface for every question. Let him put his question. Just have a little patience.

Shri R. K. Birla: The hon. Minister said that there were three kinds of woollen yarn and the prices are all fixed for the three kinds. One is hosiery, another is worsted yarn, weaving yarn and the third is knitting wool. May I know why the prices have not been fixed yet, particularly when the Government knows that on all the three kinds of yarn which contain 100 per cent imported wool, the effect of devaluation was 57.5 per cent?

Shri Shafi Qureshi: The hon. Member knows very well that the prices are already fixed. Possibly what he means is that proportional distribution in these sectors is not done properly. So far as price distribution and production and control are concerned, the report of the K. K. Shah Committee is before the Government and they will come to a decision after studying it.

श्री हुकमचन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि भारत में आकर इम्पोर्टिड ऊन किस भाव पर पड़ती है ?

श्री शफी कुरैशी : 6 रुपया 33 पैसे !

Production in Durgapur Steel Plant:

+

*245. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Manibhai J. Patel:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:
Shri Sradhakar Supakar:
Shri Ram Kishan Gupta:

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 785 on the 7th April, 1967 and state:

(a) whether the Report of the Committee headed by Shri G. Pande regarding the shortfall in the production of Durgapur Steel Plant has since been received; and

(b) if so, the findings thereof?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): (a) Yes, Sir.

(b) A summary of the Report and the recommendations is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-505/67].

श्री मधु लिमये : जो सारांश हमारे सामने रखा गया है उसके पहले पृष्ट पर वाक्य है कि प्लाट मैनेजमेंट को ज्यादा अधिकार दिये गए थे । इतने अधिकार देने के बाद भी आगे लिखा है :

"....the management seemed to have neglected many essential responsibilities like proper maintenance, lack of rigid control on quality of products, checking staff indiscipline and building up of staff competence."

कोक ओवन प्लांट के बारे में कहा गया है :

"The damage has been caused by wrong operating practices, neglecting maintenance, and ineffective inspections and this is in spite of ample warnings having been received in the past."